

From: "Sunil Kumar Gupta, TRAI" <[pradvbcs@traigov.in](mailto:pradvbcs@traigov.in)>  
Date: Oct 25, 2016 2:17:21 PM  
Subject: Fwd: TRAI releases draft Telecommunication (Broadcasting and Cable Services)Tariff Order, 2016, के लिए सुझाव  
To: [vk.agarwal@traigov.in](mailto:vk.agarwal@traigov.in)

----- Forwarded Message -----

**Subject:**TRAI releases draft Telecommunication (Broadcasting and Cable Services)Tariff Order, 2016, के लिए सुझाव

**Date:**Tue, 25 Oct 2016 07:33:54 +0000 (UTC)

**From:**Govind Patel <[govindspatel@yahoo.com](mailto:govindspatel@yahoo.com)>

**Reply-To:** Govind Patel <[govindspatel@yahoo.com](mailto:govindspatel@yahoo.com)>

**To:**pradvbcs@traigov.in <[pradvbcs@traigov.in](mailto:pradvbcs@traigov.in)>,vk.agrawal@traigov.in <[vk.agrawal@traigov.in](mailto:vk.agrawal@traigov.in)>

TRAI releases draft Telecommunication (Broadcasting and Cable Services)Tariff Order, 2016, के लिए सुझाव

आदरणीय

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली

विषय - टेलीकम्यूनिकेशन (ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विसेस) टैरिफ आर्डर 2016 के लिए सुझाव।

महोदय,

ट्राई के नए टेलीकम्यूनिकेशन (ब्राडकास्टिंग एवं केबल सर्विसेस) टैरिफ आर्डर 2016 मसौदे के लिए मेरे सुझाव निम्नलिखित हैं। मैं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश का आम उपभोक्ता हूँ, जिसे आप समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति मान सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी योजना की सफलता का आकलन करना है तो यह देखें कि उस योजना से अंतिम व्यक्ति पर कितना असर हो रहा है। इस लिहाज से मैं केबल और डीटीएच संबंधी कुछ शिकायत और सुझाव भेज रहा हूँ।

1. डीटीएच लागू करके भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। लेकिन इसे लेकर विभिन्न कंपनियों में जिस तरह की मारकाट मची है, उससे आम उपभोक्ता परेशान है। सरकार को केबल डिटिलाइजेशन की अनिवार्यता के एडवर्टाइजमेंट में इसका प्रचार करना चाहिए कि डीटीएच के माध्यम से लोग मुफ्त में टीवी चैनल देख सकते हैं। अभी डिटिलाइजेशन का मतलब

लोग टाटा स्काय, डिश टीवी, एयरटेल, रिलाइंस, सन या केबल आपरेटर के सेट-अप बाक्स ही समझते हैं। जबकि भारत सरकार ने 90 के दशक में लगने वाले बड़े डिश एंटीना से मुक्ति देने डीटीएच लांच की है। इस बात का भरपूर प्रचार करना चाहिए की डीटीएच (डीडी डायरेक्ट) लगाकर लोग मुफ्त में बहुत सारे फ्री टू एयर चैनल देख सकते हैं।

2. डिटिलाइडेशन का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिल रहा है क्योंकि शहरों में केबल आपरेटर अपना केबल बिछाकर लोगों को ज्यादा मनोरंजक चैनल दिखाते थे। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए केवल डीडी वन और डीडी न्यूज चैनल ही देख पाते थे, लेकिन नए डिश से उनके सामने ज्यादा चैनल फ्री में देखने का अवसर है, लेकिन डीटीएच (डीडी डायरेक्ट) का प्रचार नहीं होने के कारण लोग केवल निजी कंपनियों के डिश लगवा रहे हैं। जबकि सबसे ज्यादा डीटीएच ही लगने चाहिए। इसका उपभोक्ताओं का फायदा यह होगा कि डीटीएच (डीडी डायरेक्ट) प्लेटफार्म पर आने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल फ्री में आने की कोशिश करेंगी क्योंकि डीटीएच(डीडी डायरेक्ट) के उपभोक्ता ज्यादा होंगे।

3. कृपया टाटा स्काय, एयरटेल, डिश टीवी जैसी कंपनियों में भी फ्री-टू- एयर के चैनलों को मुफ्त में दिखाने की अनिवार्यता की जाए। यदि उपभोक्ता कोई पैकेज नहीं लेना चाहता तो उसे डीडी वन, डीडी न्यूज के साथ फ्री टू एयर वाले चैनल मुफ्त में देखने को मिले। वर्तमान में सभी कंपनियां टाप अप (शुल्क की अवधि) खत्म होने के बाद पूरा प्रसारण ही बंद कर देते हैं, इस वजह से लोगों को मजबूरी में महंगा टाप-अप कराना पड़ता है।

4. ट्राई ने जिस तरह से मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी का क्रांतिकारी आदेश दिया था उसी तरह सेट-अप-बाक्स में भी पोर्टिबिलिटी का आदेश दिया जाना चाहिए। वर्तमान में उपभोक्ता यदि टाटा स्काय या किसी अन्य कंपनी का सेट-अप बाक्स खरीद लेता है और उसे कुछ महीने बाद इसका पैकेज पसंद नहीं लगता तो भी वह दूसरी कंपनी नहीं बदल सकता। इसके लिए उसे नए सिरे से दूसरी कंपनी का सेट-अप बाक्स खरीदना पड़ता है। इस तरह उपभोक्ता को कंपनी बदलने के लिए हर बार सेट-अप बाक्स खरीदना पड़ता है। यदि सेट-अप बाक्स एक ही हो उसमें सिम की तरह अलग-अलग कंपनी का कार्ड डालने की सुविधा हो तो यह बहुत बेहतरीन सुविधा हो सकेगी।

5. शहरों में केबल आपरेटर भारी मनमानी करते हैं। वे जब चाहे कोई भी चैनल बंद कर देते हैं। कभी एनडीटीवी इंडिया तो कभी आजतक न्यूज चैनल बंद कर देते हैं। उपभोक्ता शिकायत किससे करें यह दुविधा का प्रश्न है। कौन इस पर अंकुश लगाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन में एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. जो शिकायतों का निराकरण करे और केबल आपरेटरों की मनमानी पर अंकुश लगाए।

6. केबल आपरेटर से एक बार सेट-अप बाक्स खरीदने पर वे उसे वापस लेने से इनकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है तो उसका पुराने केबल आपरेटर का सेट-अप बाक्स कोई काम का नहीं रहता। उसे नए शहर के केबल आपरेटर से नया सेट-अप बाक्स खरीदना पड़ता है। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ता है। इससे देश का पैसा अनुपयोगी हो जाता है।

कृपया मेरे इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का कष्ट करें। साथ ही यदि कोई और स्पष्ट शिकायत देनी हो तो उसकी भी जानकारी दें।

धन्यवाद

गोविन्द पटेल

पता- बजरंग चौक धमधा

जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ)

पिन- 491331

मोबाइल- 09893172336

ई-मेल [govindgpatel@gmail.com](mailto:govindgpatel@gmail.com)